

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

.....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 976

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

976. श्री परिमल नथवानी :

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के उद्देश्य क्या-क्या हैं;
(ख) यह अभियान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा है;
(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कौन-कौन से राज्य पिछड़ गए हैं; और
(ङ) इस अभियान का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) और (ख) : निर्मल भारत अभियान, जिसका पुराना नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था, के अंतर्गत अक्टूबर 2012 तक परियोजना उद्देश्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

घटक	अनुमोदित उद्देश्य	संचयी उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	6,18,38,922	4,81,14,035	77.81
गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	6,38,87,805	4,13,04,643	64.65
कुल-वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय	12,57,26,727	8,94,18,678	71.12
स्कूलों में शौचालय	1375234	12,53,429	91.14
आंगनवाड़ियों में शौचालय	5,34,931	4,22,166	78.92
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	33,684	24,895	73.91

(ग) : चूँकि निर्मल भारत अभियान/संपूर्ण स्वच्छता अभियान मांग आधारित योजना है, इसलिए ग्यारहवीं योजना के दौरान कोई राज्य-वार लक्ष्य तय नहीं किए गए । तथापि, वैयक्तिक

पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल), स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की राज्य वार उपलब्धि अनुबंध I में दर्शाई गई है।

(घ) : प्राप्त सूचना के अनुसार, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण में जम्मू और कश्मीर, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, दादरा व नगर हवेली तथा पुदुचेरी का निष्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ङ) : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) में आमूल-चूल बदलाव किया है, जिसका नाम अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्मल भारत अभियान हो गया है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य संपूर्ण समुदायों में चरणबद्ध रूप से और सैचुरेशन मोड में स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान करके व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना है, जिसका परिणाम 'निर्मल ग्रामों' के रूप में सामने आएगा। नई कार्य नीति का उद्देश्य समुदाय सैचुरेशन एप्रोच अपनाकर ग्रामीण भारत को 'निर्मल भारत' बनाना है। निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को शत-प्रतिशत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के साथ-साथ गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसानों, वास भूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांगों और महिला प्रमुखों के सभी परिवारों को शामिल करने के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन के प्रावधानों को व्यापक बनाया गया है। निर्मल भारत अभियान के तहत सभी पात्र लाभार्थियों हेतु शौचालयों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 4600 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत अधिकतम 4500 रुपए भी दिए जाने की अनुमति है और लाभार्थी के 900 रुपए के योगदान से अब एक शौचालय की कुल लागत 10,000 रुपए हो गई है। तैयार की गई स्वच्छता सुविधाओं को स्थायी बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में पानी की उपलब्धता के मुद्दे का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के साथ कन्जॉइन्ट एप्रोच अपनाई गई है। संशोधित कार्यनीति के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और क्षेत्रीय स्तर के कार्यान्वयन-कर्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों की क्षमता के विकास के लिए निधियाँ निर्धारित की गई हैं। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज जैसे अन्य राज्य विभागों के साथ तालमेल पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 'आशा' (एएसएचए) कार्यकर्त्रियों और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्यों द्वारा स्वसहायता समूहों, महिला समूहों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। संकेन्द्रित वित्तपोषण के जरिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को प्राथमिकता दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 3.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	स्कूलों में शौचालय	आंगनवाडियों में शौचालय
1.	आंध्र प्रदेश	1781908	1210294	2992202	421	58126	5225
2.	अरुणाचल प्रदेश	59196	13901	73097	95	3296	1722
3.	असम	1385358	406878	1792236	52	32231	10895
4.	बिहार	2624654	842939	3467593	330	62165	2792
5.	छत्तीसगढ़	863811	727347	1591158	240	43724	8898
6.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
7.	गोवा	2341	17522	19863	0	345	50
8.	गुजरात	1455947	1819809	3275756	711	13875	11461
9.	हरियाणा	378986	1074005	1452991	788	4303	4575
10.	हिमाचल प्रदेश	221668	714460	936128	594	15749	8312
11.	जम्मू व कश्मीर	199714	130504	330218	620	13340	207
12.	झारखंड	1187825	178724	1366549	205	30627	6580
13.	कर्नाटक	1646889	1795550	3442439	644	21011	11845
14.	केरल	399407	63374	462781	431	1830	3774
15.	मध्य प्रदेश	2472920	2921784	5394704	651	106542	21916
16.	महाराष्ट्र	1660013	2402818	4062831	4049	43734	32438
17.	मणिपुर	94948	33944	128892	283	3804	1148
18.	मेघालय	152082	65456	217538	161	7921	1610
19.	मिजोरम	43231	7882	51113	321	2222	703
20.	नागालैंड	84498	23736	108234	142	1887	951
21.	ओडिशा	1581431	969826	2551257	100	52050	17892
22.	पुदुचेरी	1057	0	1057	23	0	0
23.	पंजाब	184550	558367	742917	9	7317	4115
24.	राजस्थान	850460	2995771	3846231	329	40690	10401
25.	सिक्किम	11797	1116	12913	428	34	76
26.	तमिलनाडु	1756076	731800	2487876	260	16859	4726
27.	त्रिपुरा	63152	85259	148411	105	2632	2872
28.	उत्तर प्रदेश	4805363	6822653	11628016	1590	200441	95015
29.	उत्तराखंड	243478	304242	547720	54	2014	230
30.	पश्चिम बंगाल	1881926	1229498	3111424	769	72954	30514
	कुल	28094686	28149459	56244145	14405	861723	300943

*आईएचएचएल-वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय